संख्या-05/2021/75/कनिप्र/26-3-2021-20(37)/2020

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांक: 20 जनवरी,2021**
समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1412-13/स0क0/विकास/गोरखपुर-सबप्लान/(174)/2019-20 दिनांक 24 अक्टूबर, 2019, संख्या-1674-75/स0क0/ विकास/गोरखपुर-सबप्लान/(186)/2019-20 दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 एवं संख्या-1493-94/ स0क0/ विकास/गोरखपुर-(179)/2019-20 दिनांक 19 नवम्बर, 2019, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड बांसगांव, खोरा बाजार एवं उरूवा के निम्नलिखित सूची के अनुसार कार्य कराये जाने के संबंध में कुल आगणित लागत के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित तालिकाओं में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल रू0 361.00 लाख (रू0 तीन करोड़ इकसठ लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तालिका संख्या- 1

क्रं सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम की कुल आबादी में अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिशत	कार्य का नाम	प्राक्कलन लागत (लाखरू0)	प्रथम किश्त हेतु स्वीकृत धनराशि (लाखरू0)
1.	गोरखपुर	बांसगांव	सिगहा	64.58	इण्टरलाकिंग का कार्य	130.30	26.00
2.	गोरखपुर	बांसगांव	कूड़ाभरथ	54.59	इण्टरलाकिंग का कार्य	181.55	36.00
3.	गोरखपुर	बांसगांव	गुआर	69.12	इण्टरलाकिंग का कार्य	88.96	18.00
4.	गोरखपुर	बांसगांव	धुसना	59.60	इण्टरलाकिंग का कार्य	72.04	12.00
					योग-1	**472.85**	**92.00**

तालिका संख्या- 2

क्रं.सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम की कुल आबादी में अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिशत	कार्य का नाम	प्राक्कलन लागत (लाखरू0)	प्रथम किश्त हेतु स्वीकृत धनराशि (लाखरू0)
1.	गोरखपुर	खोराबाजार	सनहा	56.1	सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन का निर्माण कार्य	78.15	16.00
2.	गोरखपुर	खोराबाजार	सेमरौना	56.96	सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन का निर्माण कार्य	83.35	17.00
3.	गोरखपुर	खोराबाजार	सोनवे	58.70	सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन का निर्माण कार्य	83.45	17.00
4.	गोरखपुर	खोराबाजार	नौवा अव्वल	53.92	सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन का निर्माण कार्य	89.40	18.00
					योग-2	**334.35**	**68.00**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका संख्या- 3

क्रं सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम की कुल आबादी में अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिशत	कार्य का नाम	प्राक्कलन लागत (लाखरू0)	प्रथम किश्त हेतु स्वीकृत धनराशि (लाखरू0)
1.	गोरखपुर	उरूवा	नरायनपुर	51.91	इण्टरलाकिंग का कार्य	246.33	49.00
2.	गोरखपुर	उरूवा	अराव जगदीशपुर	50.93	इण्टरलाकिंग का कार्य	256.60	51.00
3.	गोरखपुर	उरूवा	रसूलपुर माफी	50.78	इण्टरलाकिंग का कार्य	258.17	52.00
4.	गोरखपुर	उरूवा	पहाड़पुर	50.47	इण्टरलाकिंग का कार्य	247.32	49.00
					योग-3	**1008.42**	**201.00**
					महायोग-1+2+3	**1815.62**	**361.00**

शर्ते/प्रतिबन्ध:-

1- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (सिडको) को नामित किया जाता है।

2- निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (सिडको) से शीघ्र एम.ओ.यू. अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को औपचारिकताएं पूर्ण कराकर उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कराते हुए प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष कार्यो को पूर्ण कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र निदेशक समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त कार्य मद में अधिष्ठान व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र अवशेष कार्यो को पूरा किया जायेगा। प्रयोजना के निर्माण के बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए निर्माण इकाई उत्तरदायी होगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मानक एवं दिशा निर्देशों तथा योजना संचालन संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं निर्माण संबंधी भारत सरकार की समस्त गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी तथा इसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी उत्तदायी होगें।

6- प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्रांइग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

7- संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

8- स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ.प्र. प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगित/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स, योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सदुपयोग प्रमाण पत्र इत्यादि देना सुनिश्चित किया जायेगा।

10- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल प्रस्तर 212 मे दिये गये निर्देशो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

12- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटिरिंग भी किया जायेगा।

14- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

15- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020-बी-1-149-दस/2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-04-2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-05-2020 एवं शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29-09-2020 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-26/दस/2021 दिनांक 16 जनवरी, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ.संख्या-05 /2021/75/(1)/क.नि.प्र./26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

4- जिलाधिकारी,गोरखपुर।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी गोरखपुर।

6- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

7- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गोरखपुर।

8- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (सिडको) उ0प्र0 लखनऊ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।